

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4153
जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है।
05 चैत्र, 1947 (शक)

संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अंतर्गत लाभ

4153 डॉ. मन्ना लाल रावत :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का राजस्थान राज्य के जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए किसी योजना का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) को अक्षमता और उच्च अग्रिम लागत को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए एअिसूचित किया गया था। इस योजना में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधाओं (एसईजेड इकाइयों में स्थापित इकाइयों के लिए 20% और गैर-एसईजेड इकाइयों के लिए 25%) की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की 44 श्रेणियों/कार्यक्षेत्रों और संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को शामिल करने वाले घटकों के लिए उपलब्ध है।

एम-

एसआईपीएस एक अखिल भारतीय योजना थी और यह राजस्थान राज्य सहित देश के भीतर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए एमएसएमई सहित आवेदकों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए खुली थी।

एम-एसआईपीएस के अंतर्गत राजस्थान राज्य में 11 आवेदनों को 143.35 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन संवितरित किया गया है। आवेदनों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ): एम-एसआईपीएस अखिल भारतीय योजना थी। इस योजना से उत्पन्न होने वाले लाभ किसी विशेष भूगोल या किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं हैं जहां विनिर्माण इकाई स्थित है। वास्तव में, लाभों के राष्ट्रीय स्तर पर वितरण का प्रयत्न है।

अनुबंध- I

क्र.सं	आवेदककानाम	जिला	वित्तीयवर्ष 16-17	वित्तीयवर्ष 17-18	वित्तीयवर्ष 18-19	वित्तीयवर्ष 19-20	वित्तीयवर्ष 20-21	वित्तीयवर्ष 21-22	वित्तीयवर्ष 22-23	वित्तीयवर्ष 23-24	वित्तीयवर्ष 24-25
1.	जीनसपावरइंफ्रास्ट्रक्चरलिमिटेड	जयपुर	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	निडेकइंडियाप्राइवेटलिमिटेड	अलवर	-	12.67	-	-	7.96	5.23	1.99	-	-
3.	सिक्वोरमीटर्सलिमिटेड	उदयपुर	-	4.6	-	0.8	-	-	-	6.88	-
4.	डाइकिनएयरकंडीशनिंगइंडियाप्राइवेटलिमिटेड	अलवर	-	-	3.67	-	-	-	-	-	-
5.	भगवतीइलेक्ट्रॉनिकी	अलवर	-	-	1.79	1.51	-	-	10.52	-	-
6.	पर्टो	जयपुर	-	-	-	13.58	-	-	-	-	-
7.	ओरिएंटकेबल	अलवर	-	-	-	2.41	-	-	-	-	-
8.	हैवेल्स	अलवर	-	-	-	-	30.9	3.72	-	3.21	-
9.	डाइकिनएयरकंडीशनिंगइंडियाप्राइवेटलिमिटेड (एप्लीकेशन -02)	अलवर	-	-	-	-	24.22	-	-	-	-
10.	निडेकइंडियाप्राइवेटलिमिटेड (एप्लीकेशन - 02)	अलवर	-	-	-	-	-	-	-	1.91	-
11.	निडेकइंडियाप्राइवेटलिमिटेड (एप्लीकेशन -03)	अलवर	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
	कुल		2.8	17.27	5.46	18.3	63.08	8.95	12.51	12	2.9
